नई दल्लिी□ अर्थव्यवस्था की बेहतर तस्वीर पेश करते हु□ वत्ति मंत्री पी. चदिंबरम ने आज कहा कि मौजूदा दबाव के बावजूद चालू वत्ति वर्ष में देश की आर्थकि वृद्धि दर 5 प्रतशित रहेगी□

यहां □ क संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा, ''हम दबाव के दौर से गुजर रहे है, लेकनि उम्मीद अब भी कायम है... हमें उम्मीद है कि चालू वत्ति वर्ष की दूसरी छमाही में चीजें बेहतर होंगी□ ''

वत्ति मंत्री ने दूसरी तमिाही में उम्मीद से बेहतर 4.8 प्रतशित की वृद्धि दर, चालू खाते के घाटे में सुधार और नरि्यात में तेजी लौटने सहति वभिन्नि कारकों के आधार पर यह उम्मीद जाहरि की□

चदिंबरम ने कहा कि चालू वत्ति वर्ष में आर्थकि वृद्धि दर 5 प्रतशित रहने की संभावना है□

उन्होंने कहा, ''दूसरी तमिाही की जीडीपी वृद्धि दर से संकेत मलिता है कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है और दूसरी तमिाही का नष्पिादन अनुमान के मुताबकि रहा□ ''

वत्ति मंत्री ने कहा कि वनिरि्माण, नरि्यात क्षेत्र का बेहतर नष्पिादन जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हाल के सुधार और सरकार द्वारा कि□ ग□ उपायों से अर्थव्यवस्था में और सुधार आने की संभावना है□

चदिंबरम ने यह भरोसा भी जताया कि सरकार 40,000 करो□ रूप□ का वनिवेश लक्ष्य हासलि करने में समर्थ रहेगी और साथ ही वह राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.8 प्रतशित के भीतर रखने में कामयाब रहेगी□

उन्होंने कहा, ''हमारी नजर अब भी लक्ष्य पर है□ हम 40,000 करो□ रूप□ का वनिवेश लक्ष्य हासलि करने की दशिा में हैं□ ''

चदिंबरम ने कहा कि चालू वत्ति वर्ष की पहली छमाही में राजकोषीय घाटा ऊंचा रहा□ ''कसिी भी माह के अंत में राजकोषीय घाटा सही तस्वीर पेश नहीं करता क्योंकि खर्च आमतौर पर अधकि होता है और राजस्व पीछे होता है□ हम राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.8 प्रतशित पर रखेंगे□ ''

वर्ष 2013-14 के प्रथम सात महीनों (अप्रैल-अक्तूबर) में राजकोषीय घाटा पूरे साल के बजट अनुमान के 84.4 प्रतिशत पर पहुंच गया।

चिदंबरम ने कहा कि अक्तूबर अंत में योजनागत व्यय, बजट अनुमान का 48.3 प्रतिशत रहा जो पिछले साल 43.2 प्रतिशत था। अक्तूबर तक शुद्ध कर व गैर कर राजस्व, बजट अनुमान का 43.2 प्रतिशत रहा जो पिछले साल भी इसी स्तर पर था।

वित्त मंत्री ने कहा, ''दूसरी छमाही की शुरूआत में कुछ हलचल दिखी है। हम कर संग्रह में तेजी लाएंगे और राजस्व संग्रह में तेजी आते ही हमें उम्मीद है कि हम राजकोषीय घाटे को लक्ष्य के भीतर रखने में सफल रहेंगे।''

उन्होंने कहा कि सरकार स्पेक्ट्रम की बिक्री से 40,000 करोड़ रूपए के बजट अनुमान से अधिक राशि प्राप्त करेगी।

मुद्रास्फीति के संबंध में पूछे गए सवाल पर चिदंबरम ने कहा कि खाद्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने की प्रधान जिम्मेदारी और सभी उपकरण राज्य सरकारों के पास है।

''पिछले कई सालों से राज्य सरकारें बड़ी सहजता से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती रही है और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराती रही है। लेकिन, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है, लेकिन खाद्य मुद्रास्फीति से निपटने की बड़ी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।''

''उन्हें जमाखोरी और मुनाफाखोरी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए .. उन्हें व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करना चाहिए और आपूर्ति में सुधार के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए।।''

उल्लेखनीय है कि उच्च खाद्य कीमतों के चलते अक्तूबर में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 10.09 प्रतिशत पर पहुंच गई। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अक्तूबर में 8 माह के उच्च स्तर 7 प्रतिशत पर रही।

(भाषा)